ईडलवाइज
आइडियाज क्रिएट, वेल्यूज प्रोटेक्ट

कांफ्रेंस कॉल प्रतिलिपि

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
वित्तीय वर्ष 13 की तिमाही 1 के परिणाम
9 अगस्त, 2012. सायं 4.00 बजे भारतीय मानक समय

नैगमिक भागीदार

श्री सतनाम सिंह

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

प्रश्न और उत्तर

———————————————————————————————————————

संचालक : देवियो और सज्जनो, नमस्कार और ईडलवाइज सिक्योरिटी लिमि. की मेजबानी में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तिमाही 1 वित्तीय वर्ष 13 की आय संबंधी सम्मेलन कॉल में आपका स्वागत है। सम्मेलन की अवधि के आरंभिक भाग में सभी भागीदार क्षेत्रों को केवल सुनना होगा और आपको आज के प्रस्तुतीकरण के अंत में प्रश्न पूछने का अवसर दिया जायेगा। सम्मेलन कॉल के दौरान यदि आपको सहायता की जरूरत होती है तो आप अपने टच टोन टेलीफोन पर * और तत्पश्चात 0 दबाकर प्रचालक को संकेत दे सकते हैं कृपया नोट करें कि इस सम्मेलन को रिकॉर्ड किया जा रहा है अब मैं इस सम्मेलन का मंच ईडलवाइज के श्री कुणाल शाह को देना चाहूंगा। धन्यवाद, अब आपकी बारी है महोदय।

कुणाल शाह : धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार मैं ईडलवाइज सिक्योरिटी से कुणाल शाह हूं। हमारे साथ श्री सतनाम सिंह – अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैं, जो अपनी तिमाही 1 वित्तीय वर्ष 13 की आय पर चर्चा करेंगे और विद्युत क्षेत्र में कुछ अद्यतन गतिविधियों के बारे में अपना परिपेक्ष्य बताएंगे। महोदय, इतने अच्छे आंकड़ों के लिए आपको बधाई और अब आगे की कार्यवाही आप संभालेंगे।

सतनाम सिंह : सभी को नमस्कार। मैं आश्वस्त हूं कि आप में से अधिकांश ने हमारे परिणाम देखे होंगे परंतु इस सम्मेलन के लिए मैं सोचता हूं मैं अपनी चर्चा को तीन स्तरों में विभाजित करूंगा। पहला स्तर वित्तीय है, दूसरा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अन्य गतिविधियों के बारे में है और तीसरा ऐसी क्षेत्रीय गतिविधियों से संबंधित है जिनके हमारे निगम पर निहतार्थ हैं; सबसे पहले व्यावसायिक वृद्धि को देखते हैं, तिमाही के दौरान हमारे संवितरण में 29 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जो 6099 करोड़ रुपए से 7884 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारी ऋण परिसम्पत्तियों में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 1,04,050 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,34,742 करोड़ रुपए हो गए हैं। हमारी कुल आय में 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है जो 2924 करोड़ रुपए से बढ़कर 3945 करोड़ रुपए हो गई है। हमारी निवल ब्याज आय में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 990 करोड़ रुपए से बढ़कर 1394 करोड़ रुपए रुपए हो गई है। इन सभी के परिणामस्वरूप हमारे कर पश्चात लाभों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 972 करोड़ रुपए हो गए हैं। विस्तार और एनआईएम में 35 मूल बिन्दु और 34 मूल बिन्दु की वृद्धि हुई है जो क्रमशः 2.28 प्रतिशत से 2.63

प्रतिशत और 3.85 प्रतिशत से 4.19 प्रतिशत हो गए हैं। आप में से वे लोग जिन्होंने पिछले सम्मेलन कॉल में मुझे सुना है, मैंने बिलकुल स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा विस्तार पिछली बार केवल इसलिए कम था क्योंकि आरबीआई लगातार ब्याज दर बढ़ाता रहा था और जिस क्षण आरबीआई ने ब्याज दर में इस तरह की वृद्धि पर रोक लगाई, तब से हमारा विस्तार सामान्य स्तर पर आ जाएगा और मेरी बात सच हुई। इसलिए आगे भी यदि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों को स्थिर रखता है तो हम अपने विस्तार को इसी दायरे में बनाए रखेंगे।

मार्च के अंत तक हमारे पूंजी पर्याप्तता अनुपात में हमने इसे 16.29 प्रतिशत के स्तर पर दर्शाया है परन्तु 30 जून की स्थिति के अनुसार ये 18.55 प्रतिशत है, प्राथमिक रूप से इसका कारण यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले से पूरी परियोजनाओं और ऐसी परियोजनाओं जिनका एक वर्ष में प्रचालन 100 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक संतोषजनक रहा है, के लिए जोखिम घटक को कम कर दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के इस नए परिपत्र के कारण हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़कर 1.88 प्रतिशत हो गया है।

तिमाही के दौरान हमारी गैर–निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हमारी सकल एनपीए में 1.04 प्रतिशत से 1.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है जो प्राथमिक रूप से ऋण परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण हुई है और निवल एनपीए में भी 0.93 प्रतिशत से 0.91 प्रतिशत की गिरावट आई है।

अब आगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में होने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। सबसे पहले कल की बोर्ड की बैठक में हम सभी ने भारत से बाहर की ऊर्जा सुरक्षा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का निर्णय लिया है और मैं आश्वस्त हूं कि आप में से अधिकांश को इस बात की जानकारी होगी। विडियोकॉन ने मोजाम्बिक, ब्राजील और इण्डोनेशिया में गैस क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है जहां भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई ने उन परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है। हमने भी इसमें भागीदारी की है और 2200 करोड़ रुपए का वित्तपोषण करने पर सहमति जताई है। इसी प्रकार जीवीके जिसने आस्ट्रेलिया में कोयला खदानों का अधिग्रहण किया है और इस समय इन कोयला खदानों का विकास कर रहा है, उनके साथ अग्रणी बैंक आईसीआईसीआई ने भागीदारी की है और 155 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई है। वास्तव में यह भारतीय रिजर्व बैंक के उस अनुमोदन से जुड़ा हुआ है जिसमें उसने विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा उधार देने में हमें सक्षम बनाया है। ऐसी कम्पनियों को वित्तीय सहायता देने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि वे इन

परियोजनाओं से होने वाले उत्पादन को भारत को देंगे जिससे भारतीय विद्युत परियोजनाओं में ईंधन की आपूर्ति में मदद मिलेगी।

पहली तिमाही के दौरान हमने 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का एक सामूहिक ऋण लिया है जिसके लिए करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं और हमें शीघ्र ही यह धनराशि मिलने की संभावना है। अब तक हमने पहली तिमाही में बॉन्ड और एफसीएनआरके रोल ओवर से लगभग 8600 करोड़ रुपए जुटाए हैं, इसी के साथ कुछ दिन पहले हमने एक और इश्यू जारी किया है, तथापि घरेलू बाजार में हमें 4100 करोड़ रुपए मिले हैं। इसलिए समग्र रूप से हमने लगभग 14000 करोड़ रुपए की निधि पहले ही जुटा ली है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय हमें 5000 करोड़ रुपए के कर – मुक्त बॉन्ड देने पर सहमत हुआ है और जैसे ही वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है हम इस कर मुक्त बॉन्ड को लाएंगे। इसी के साथ जहां तक संसाधन जुटाने का संबंध है हम वार्षिक लक्ष्य का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त कर लेंगे।

जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधीन मानकों के लागू होने का संबंध है, हमने तत्संबंधी रूपरेखा को पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया है। मैं आश्वस्त हूं कि आप इसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने हमें इस प्रावधान के साथ मार्च, 13 तक की छूट दी है कि पीएफसी को मार्च 2016 तक केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की कम्पनियों के मानकों का अनुपालन करना होगा परन्तु हमने भारतीय रिजर्व बैंक को बताया है कि ऐसा करना उचित नहीं है, परन्तु हमने विद्युत मंत्रालय की मदद से 12वीं योजना के अंत तक की छूट मांगी है और तत्पश्चात हमने यह कहा है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

आरबीआई ने एक अन्य परिपत्र भी जारी किया है जिसमें वे चाहते हैं कि आईएफसी नहीं दी गई वचनबद्धताओं के लिए भी लगभग 50 प्रतिशत की सीमा तक पूंजी पर्याप्तता उपलब्ध कराए। जब हमने यह मामला उनके साथ उठाया तो उन्होंने कहा कि इसका समाधान वर्ष–दर–वर्ष आधार पर मंजूरी जारी करके किया जा सकता है परन्तु ऐसी विद्युत परियोजनाओं, जहां वित्तीय मंदी, उसकी वित्तीय सहायता के लिए धनराशि देने हेतु किसी ऋणदाता की एक शर्त है, वहां यह करने योग्य नहीं है। यद्यपि, हमें मार्च 13 तक की छूट मिली है, हमने इस मामले को पुनः भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया है कि विद्युत परियोजनाओं के लिए धन देने वाली वित्तीय कम्पनियों को नहीं ली गई वचनबद्धताओं के लिए अतिरिक्त पूंजी देने से छूट प्रदान की जाए। देखते हैं वे इस पर क्या उत्तर देते हैं।

इसके अलावा हमने अपने परामर्शी स्कंध के लिए संयुक्त उद्यम बनाने की इच्छा की अभिव्यक्ति की मांग की है तापीय विद्युत क्षेत्र में अनुभव वाली किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के संबंध में बोली प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। जब भी बोलियां प्राप्त होती हैं हम उनके बारे में आपको बताएंगे। हमने पावर इक्विटी फण्ड भी जारी किया है, वास्तव में इसे शुरू नहीं किया है बल्कि हमने यह निर्णय लिया है कि हम इसे पावर इक्विटी फण्ड के लिए पहला भागीदार किसे बनाएंगे। कल बोर्ड ने टाटा कैपिटल का नाम अनुमोदित किया है वस्तुतः चार कंपनियों के साथ विचार–विमर्श किया गया था – टाटा कैपिटल, रैलीगेयर, रिलाइन्स और इडलवाईस। इस प्रकार हमने सबसे पहले टाटा कैपिटल के साथ जाने का निर्णय लिया है। यदि हम विस्तृत निबंधन और शर्तों पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो संभवतः बाद में हम रैलीगेयर के साथ जाएं।

हमारी दो अतिरिक्त सहायक कम्पनियों, पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विस और पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमि. में से पीएफसीसीएएस ने पहले से लाभ कमाना शुरू कर दिया है, पिछले वर्ष उसने 5 लाख रुपए का लाभ कमाया है, पहली तिमाही में यह लगभग 15 लाख रुपए है और पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमि. ने एनडीएफसी दर्जे हेतु आवेदन किया है और संभवतः यह हमें एक महीने में मिल जायेगा परन्तु इस क्षेत्र में हमने 1563 करोड़ रुपए का व्यापार किया है और हम इसे एनबीएफसी दर्जा मिलते ही इस सहायक कम्पनी को हस्तांतरित कर देंगे।

अब अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के संबंध में; जैसा हम सभी जानते हैं 16 को अभिज्ञात किया गया था, 4 को सफलतापूर्वक सौंपा गया है, उनमें से 2 के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ में काफी समय पहले हमने आरएफक्यू जारी कर दिया है। ओडिशा आरएफक्यू के लिए मूल्यांकन किया गया है और हम विद्युत मंत्रालय से आरएफपी के लिए नये दस्तावेज, संशोधित दस्तावेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अभी भी एक वर्जित क्षेत्र है। हम स्थानीय आंदोलन के कारण तकनीकी अध्ययन नहीं करवा पा रहे हैं। अगला यूएमपीपी जो चेय्यूर में अंतिम स्तर पर है तथा जो आयातित कोयला आधारित है, उसके लिए हम आरएफक्यू जारी करने हेतु तैयार हैं तथापि, इस यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू नए दस्तावेजों के आधार पर ही जारी किया जा सकता है जो अभी विद्युत मंत्रालय से प्राप्त नहीं है। ओडिशा में दो नए अतिरिक्त यूएमपीपी के लिए स्थल की पहचान कर ली गई है और कार्य प्रगति पर है। झारखंड में हमने दूसरे यूएमपीपी स्थल की पहचान कर ली है और हमने उसके लिए देवघर मेगा पावर लिमि. के नाम से एसपीवी भी सृजित की है। इस यूएमपीपी के लिए स्थल हुसैनाबाद है और हम कोयला खदान के आबंटन की संभावना तलाश रहे हैं।

इसी प्रकार स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजना के संबंध में 4 का कार्य पहले ही सौंपा गया है। हम पांचवें आईटीपी, जो उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी है, के संबंध में कार्य रहे हैं; आरएफक्यू शीघ्र जारी होने की संभावना है।

पुनर्गठित एपीडीआरपी योजना कार्यान्वयन के अंतिम स्तर पर है, अब तक 9 राज्यों को समेकित किया गया है। एक प्रायोगिक कस्बे के साथ डाटा सेन्टर और प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है। 1400 कस्बों में से 201 कस्बों को समेकित किया गया है। हमें 4 राज्यों में 95 कस्बों के लिए आंकड़े प्राप्त हुए हैं, इस तरह की तैयारी संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के साथ वे सकल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटों को औसतन लगभग 6.5 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम होंगे।

और अंततः डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति के बारे में मैं आश्वस्त हूं कि आप जानते हैं कि डिस्कॉम के लिए पुनर्गठन पैकेज वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है और उसे मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जा रहा है। यह पुनर्गठन पैकेज वितरण कम्पनी के लिए बैंक द्वारा अल्पावधिक ऋण हेतु है और विद्युत मंत्रालय ने हम से 6 राज्य स्तरीय डिस्कॉम के लिए इसी प्रकार की मदद प्रदान करने का अनुरोध किया है। निस्संदेह इन डिस्कॉम के लिए हमारा ऋण काफी कम 5820 करोड़ रुपए दीर्घावधिक ऋण और 1890 करोड़ रुपए अल्पावधिक ऋण है। हम इनमें से किसी ऋण का पुनर्गठन करने पर सहमत नहीं हुए हैं परन्तु क्योंकि इन डिस्कॉम को बैंकों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे वित्तीय पुनर्गठन योजनाओं के पश्चात भी नकद की कमी है। इसलिए हम उन्हें सहायता देने पर सहमत हुए हैं और यह सहायता 6 राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ से 5000 करोड़ रुपए के बीच है और हम तीन वर्ष की अधिकतम आस्थगन अवधि और 7 वर्ष तक की अधिकतम वापसी भुगतान अवधि की पेशकश कर रहे हैं। यह धनराशि राज्य सरकार की गारंटी वाली सिक्योरिटी के साथ मंजूर की जाएगी और अब तक हमने इसके विरुद्ध कोई धनराशि वितरित नहीं की है परन्तु हमने सभी 6 राज्यों के साथ चर्चा सम्पन्न कर ली है। यह सभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की गतिविधियां रही हैं।

अब डिस्कॉम में हुई गतिविधियों से इतर विद्युत क्षेत्र की अन्य गतिविधियां कोयला और एफएसए के मुद्दे के बारे में रही हैं। मैं आश्वस्त हूं कि आप में से कुछ ने परसों सीआइएल बोर्ड के निर्णय को निश्चित रूप से देखा होगा। वे ग्रेड आधार पर 1.5 प्रतिशत से 40 प्रतिशत का जुर्माना लगाने पर सहमत हुए हैं। इसका वास्तव में अर्थ यह है कि चूंकि 65 प्रतिशत से कम का जुर्माना काफी बढ़ जाता है, 60 से 65 प्रतिशत के बीच

यह 5 प्रतिशत है। 50 और 60 प्रतिशत के बीच यह 10–12 प्रतिशत है और 50 प्रतिशत से नीचे यह 40 प्रतिशत है, इसलिए चूंकि जुर्माना काफी अधिक है। 65 प्रतिशत से कम पर कोई यह सुरक्षित अनुमान लगा सकता है कि कोल इण्डिया यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यकता का कम से कम 65 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति की जाए और यदि ऐसा होता है तो ऋणदाताओं के लिए किसी चूक की संभावना नहीं रहेगी। हमने समग्र क्षमताओं के मुकाबले कोयला आधारित तथा गैस आधारित अपनी दोनों तरह की वित्तपोषित परियोजनाओं का निस्संदेह अध्ययन किया है जो आईपीपी के लिए लगभग 50,600 मेगावाट है और राज्य क्षेत्र तथा केन्द्र क्षेत्र के लिए लगभग 40,000 मेगावाट है मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रीय परियोजनाओं को कोल इण्डिया से कोयले की आपूर्ति मिलेगी। आईपीपी यदि उन्हें हमारे नजरिये से कोई समस्या होती है तो हमने यह विश्लेषण किया और देखा है कि वर्धा पावर के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं जहां खदाने वर्जित क्षेत्रों में हैं और एस्सार पावर जहां आबद्ध खनन के लिए वन विभाग की स्वीकृति लेनी होगी। इन दोनों परियोजनाओं में हमारा संवितरण केवल लगभग 1400 करोड़ रुपए है और इन परियोजनाओं के अलावा हमें कोई खास समस्या दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार हमारी गैस आधारित परियोजनाओं में हमने 4700 मेगावाट की निजी क्षेत्र की परियोजनाओं और लगभग 7000 मेगावाट की राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं में क्षमता संबंधी सहायता की है। हमें कोनासीमा गैस जो पहले ही एनपीए बन चुका है, के अलावा कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। हमारा संवितरण लगभग 406 करोड़ रुपए है। शेष परियोजनाओं में हमें कोई समस्या नहीं है और राज्य और केन्द्र क्षेत्र की परियोजनाओं को जैसा मैंने पहले आपको बताया है किसी भी तरह से भारत सरकार के विचार–विमर्श से गैस की आपूर्ति मिलती रहेगी।

आप में से कुछ यह जानना चाहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में हमारे लक्ष्यों का क्या होगा। हमारा मंजूरी संबंधी लक्ष्य 46,000 करोड़ रुपए है। हमारा संवितरण लक्ष्य लगभग 43,000 करोड़ रुपए है और हमारा संसाधन जुटाने का लक्ष्य लगभग 40,500 करोड़ रुपए है। यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे निवल मूल्य आकार जो इस समय लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है, के आधार पर हम देश में सबसे बड़ी एनबीएफसी बन गए हैं। मैं समझता हूं कि हम आप सभी की सहायता और प्रोत्साहन के साथ सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

संचालक : सहभागियों, अब हम प्रश्न और उत्तर सत्र की शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहला प्रश्न यूबीएस सिक्योरिटी के श्री अजीतेश नायर का लेंगे। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

अजीतेश नायर : महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं, पहला परिसंपत्ति आय के संबंध में है जो इस तिमाही के दौरान काफी तेजी से बढ़ी है, इसका कारण क्या है?

सतनाम सिंह : जी हां, जैसा आप जानते हैं पिछली तिमाही में हमारे संवितरण चालू दर पर 15,000 करोड़ रुपए के रहे थे और उस पूरे 15,000 करोड़ रुपए की आय इस तिमाही में पूर्णतया प्राप्त हुई है। इसके अलावा तिमाही–वार पुनर्गठन की दृष्टि से यह तेजी से हुआ है। इस प्रकार इन दोनों चीजों के एक साथ होने के परिणामस्वरूप बढ़ोतरी हुई है।

अजीतेश नायर : परन्तु महोदय पुनर्गठन, क्या आपने अपनी बैंचमार्क दरों में परितर्वन किया है?

सतनाम सिंह : जी नहीं, हमने अपनी बैंचमार्क दरों में परिवर्तन नहीं किया है परन्तु जैसा आप जानते हैं पूववर्ती दरें कम थीं क्योंकि जहां तक पिछले कुछ महीनों का संबंध है दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।

अजीतेश नायर : दूसरा प्रश्न आपकी प्रोविजिनिंग कवरेज से संबंधित है। केवल एक सोच कि इस तिमाही में हमारे लाभ की वृद्धि काफी मजबूत रही है, जिसके जारी रहने की संभावना है। क्या ऐसा कोई विचार है कि हम अपनी प्रोविजिनिंग कवरेज को बढ़ाना चाहेंगे।

सतनाम सिंह : जी नहीं, वास्तव में हम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार–विमर्श कर रहे हैं। एक बार उस रूपरेखा संबंधी मानकों के अनुमोदित होने पर हम इसका निर्णय लेंगे। वस्तुतः हमने यह प्रस्ताव किया है कि कुछ अवधि के लिए यद्यपि हमारे पास संदेहास्पद ऋण के लिए पर्याप्त आरक्षित निधि है (जिसे मैं कुछ समय से निवेशकों को बताता रहा हूं) तथापि, हम आरबीआई के साथ चर्चा पूरी होने पर कुछ अतिरिक्त प्रावधान करेंगे।

अजीतेश नायर : यह चर्चा इस वर्ष के दौरान हुई है।

सतनाम सिंह : जी नहीं, मार्च 13 तक हमें छूट मिल गई है। इसलिए चाहे जो भी अतिरिक्त मानक हों वे 13–14 से लागू होंगे और उस समय जो भी करार रिजर्व बैंक के साथ होगा हम उसी आधार पर कार्य करेंगे। किसी भी तरह से कुल प्रावधान जिसकी वे हमसे आशा करते हैं केवल 0.25 प्रतिशत है, जो हमारे लिए कुछ खास नहीं है।

अजीतेश नायर : निस्संदेह महोदय, मेरा प्रश्न इस बारे में है कि इस चक्र को देखते हुए कि हम इसमें हैं और हमारे पास पहले ही 1 प्रतिशत का सकल एनपीए है, हमारी प्रोविजिनिंग कवरेज केवल 10 प्रतिशत है। हम काफी अच्छी आय कमा रहे हैं। क्या इन लाभों का प्रयोग हमारे तुलन पत्र में सुधार के लिए करने का कोई विचार है।

सतनाम सिंह : जी नहीं हमने ऐसा नहीं सोचा है, परन्तु 1 प्रतिशत की इन एनपीए के संबंध में मैं आश्वस्त हूं कि आप जानते हैं कि उन कम्पनियों में से एक जिनका हमने पहले से पुनर्गठन किया है तथा जो निर्धारित तारीख पर अब भुगतान कर रही है, वह इस वर्ष की चौथी तिमाही में मानक परिसंपत्तियों के रूप में वापस आ सकती है। एक बार कोनासीमा को गैस की आपूर्ति होने पर यह निर्णय अगले 2–3 महीनों में लिए जाने की संभावना है। तत्पश्चात वह भी हमारी एनपीए नहीं रहेगी। अन्य दो जिनमें से एक ओम शक्ति परियोजना है जो एक छोटी परियोजना है और दूसरी श्री महेश्वर है जिसमें हमने प्रर्वतकों को शेष इक्विटी की व्यवस्था करने के लिए कुछ हद तक समय सीमा पहले ही दे दी है। एक बार इसके होने के बाद उस परियोजना की कम–से–कम 3–4 इकाइयों में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस दृष्टि से वास्तव में किसी दबाव में नहीं हैं परन्तु हां यह बात ठीक है कि यह कुछ समय के लिए एनपीए है और हम इस मुद्दे के समाधान के लिए इसकी जांच कर रहे हैं।

संचालक : हमारा अगला प्रश्न सुन्दरम म्युचुअल फंड के श्री कृष्ण कुमार की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

कृष्ण कुमार : महोदय, आपने गैस क्षेत्र और उन परियोजनाओं के बारे में बताया जिनका हमने वित्तपोषण किया है। हमने सुना है कि आंध्र प्रदेश में अनेक परियोजनाएं गैस पर आधारित हैं, हमने इनमें से कुछ परियोजनाओं जैसे लेंकोज कोण्डापल्ली विद्युत परियोजना, जीवीके गौतमी विद्युत परियोजना या रिलायंस पावर समलकोट परियोजना को देखा है और हम इन परियोजनाओं के संबंध में इस तरह से आगे बढ़ने की मंशा रखते हैं।

सतनाम सिंह : जिन तीन परियोजनाओं का आपने उल्लेख किया है, उनमें लेंको कोण्डापल्ली से हमारा संबंध है परन्तु यह पूर्णतया प्रदत्त है जीवीके गैस परियोजना और समलकोट के लिए हमने मंजूरी दी है परन्तु प्रवर्तक ऋण लेने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हमने यदि वे परियोजनाओं के पूरा होने से पहले गैस की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं रहते हैं तो उनसे बैंक गारंटी की मांग की है। यह निबंधन उन्हें स्वीकार्य नहीं है इसलिए

इन दो परियोजनाओं के लिए हमने संवितरण नहीं किया है। आंध्र प्रदेश में एकमात्र परियोजना जिसमें हमें गैस संबंधी समस्या है कोनासीमा है और वह पहले से एनपीए बन गया है क्योंकि उन्हें पूरी गैस नहीं मिल रही है और सरकार इन सभी पर विचार कर रही है और इसकी पूरी संभावना है कि इन विद्युत परियोजनाओं को लगभग 2–3 महीने के समय में गैस मिल जाएगी ।

कृष्ण कुमार : और महोदय, उर्जा सुरक्षा परियोजनाओं में ऋण देने के संबंध में आपने वीडियोकॉन और जीवीके की कोयला खदान का उल्लेख किया। जहां तक तेल और गैस का संबंध है क्या हम इन परियोजनाओं का आकलन करने की विशेषज्ञता निर्मित करने की मंशा रखते हैं। इसलिए हम इस स्थान को ऋण देने के बारे में क्या सोचते हैं और अगले 3 वर्षों में हमें क्या लक्ष्य सोचने चाहिए, हमारे लिए एक क्षेत्र के रूप में तेल और गैस क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है।

सतनाम सिंह : जी हां, इस समय यह कहना मुश्किल है कि यह कितना बड़ा क्षेत्र होगा परन्तु मैं आपको यह बता सकता हूं कि हमने उस क्षेत्र में आगे जाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि हमारी सोच यह है कि यह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आरंभ में हमने कुल संपर्क में से बहुत थोड़ी सी भागीदारी की और हमने अग्रणी बैंकर द्वारा किये गये मूल्यांकन पर प्राथमिक रूप से भरोसा किया है। इस क्षेत्र में आरंभ में कम निवेश करने और आगे बढ़ने का विचार वास्तविक रूप से आंतरिक विशेषज्ञता विकसित करने के लिए है। यदि हमें इसी प्रकार की अगली परियोजना मिलती है तो हम अपनी टीम के सदस्यों से पूछेंगे, तकनीकी टीम के सदस्य मूल्यांकन का हिस्सा होंगे और ऐसी परियोजना की बेहतर समझ सुनिश्चित करेंगे ताकि हम एक बड़े व्यापार के विकास में इस प्रकार के व्यवसाय को विकसित कर सकें।

कृष्ण कुमार : और महोदय, पहली तिमाही में क्या आप मंजूरी के संबंध में कुछ जानकारी दे सकते हैं ताकि हम इस बारे में कुछ समझ सकें कि किस तरह की परियोजना मंजूरी दी गई है?

सतनाम सिंह : पहली तिमाही में हमने 11,182 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

कृष्ण कुमार : तो क्या यह अनिवार्य रूप से तापीय विद्युत के लिए है या यह कौन सा क्षेत्र है महोदय?

सतनाम सिंह : आपका मतलब है परियोजनाएं?

कृष्ण कुमार : जी हां।

सतनाम सिंह : परियोजनाएं नागापट्टनम पावर एंड इन्फ्रा, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेज –।।, महाराष्ट्र में इंडिया बुल्स रियल टेक फेस–।। परियोजना, सोलर थर्मल परियोजना केवीके अर्थात लेंको, दिवाकर सोलर की 100 मेगावाट सौरताप परियोजनाएं हैं। एक अन्य परियोजना महाराष्ट्र में 600 मेगावाट जिनभूविश पावर जेनरेशन, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर 250 मेगावाट हैं। इनमें से सौर क्षेत्र में दो और एक जलविद्युत को छोड़कर अधिकांश कोयला क्षेत्र में हैं।

संचालक : हमारा अगला प्रश्न मैक्वारी कैपिटल के पराग जरीवाल की ओर से है, कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

पराग जरीवाल : मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि तिमाही के दौरान आपने जो संवितरण किया है उसमें से कितना हिस्सा एक वर्ष से कम में कार्यशील पूंजी या अल्पावधिक ऋण के लिए है ?

सतनाम सिंह : 7884 करोड़ रुपए के कुल संवितरण में से कार्यशील पूंजी केवल लगभग 75 करोड़ रुपए की है।

पराग जरीवाल : और समग्र बही के प्रतिशत के रूप में कार्यशील पूंजी ऋण कितना है?

सतनाम सिंह : यह 1,35,000 करोड़ रुपए में से लगभग 4,000 करोड़ रुपए है। इस प्रकार यह 3 प्रतिशत है।

पराग जरीवाल : और महोदय आज की तारीख के अनुसार पुनर्गठन बही का बकाया कितना है? मेरा मतलब समयावधि में कुछ वृद्धि या ब्याज दरों के पुनर्गठन से भी है क्योंकि आपके समकक्ष अधिकारी के पास पुनर्गठित परिसम्पत्ति के रूप में काफी धनराशि है इसलिए इसके लिए आपकी धनराशि कितनी है?

सतनाम सिंह : हमने किसी भी मामले में कोई पुनर्गठन नहीं किया है।

पराग जरीवाल : समयावधि में भी नहीं और ब्याज दर के लिए भी नहीं?

सतनाम सिंह : जी नहीं, ब्याज के लिए हमने कभी भी पुनर्गठन नहीं किया है। राज्य क्षेत्र के मामले में वास्तव में समयावधि के लिए कुछ मामलों में हमें छूट मिली है, परियोजना पूरी करने के कार्यक्रम में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का परिवर्तन हुआ है जिसे पुनर्गठन नहीं माना गया है। इसलिए पुनर्भुगतान में भी कुछ महीने का परिवर्तन हुआ है। इसका वर्गीकरण भी पुनर्गठन के भी रूप में नहीं किया गया है।

पराग जरीवाल : इसकी कोई संख्या है?

सतनाम सिंह : जी नहीं, कोई संख्या नहीं है, यह एक छोटी संख्या है जो प्रायः नहीं होती है। मैं इस समय कोई संख्या नहीं बता सकता हूं।

संचालक : हमारा अगला प्रश्न के.आर. चोकसे से मनीष ओस्टवाल की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

मनीष ओस्टवाल : महोदय, केवल एक स्पष्टीकरण की भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी विद्युत परियोजनाओं पर जोखिम घटक को कम करता है जो पहले से शुरू हो गई हैं। मैं केवल यह यह जानना चाहता हूं कि यह सभी अवसंरचना वित्तपोषण कम्पनियों पर लागू होता है या यह विशेष रूप से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए है?

सतनाम सिंह : जी नहीं, इसकी अनुमति सभी आईएफसी के लिए है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का मानक परिपत्र है।

मनीष ओस्टवाल : और दूसरे वर्ष के दौरान कुल परिसम्पत्तियां और देयता की पुनः कीमत क्या है?

सतनाम सिंह : तिमाही 1 में किया गया पुनर्गठन लगभग 18,000 करोड़ रुपए है।

मनीष ओस्टवाल : परिसम्पत्ति पक्ष में?

सतनाम सिंह : जी हां।

मनीष ओस्टवाल : और देयता पक्ष के संबंध में?

सतनाम सिंह : देयता के संबंध में पहली तिमाही के लिए हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं परन्तु यदि आप ई–मेल करें तो हम आपको इन्हें उपलब्ध कराएंगे।

मनीष ओस्टवाल : और महोदय, दूसरा यह कि इस समय परिसम्पत्ति देयता की अवधि कितनी है?

सतनाम सिंह : 6.15 वर्ष और 5.82 वर्ष।

मनीष ओस्टवाल : और अंततः विदेशी मुद्रा ऋण पक्ष के संबंध में कुल बकाया उधार में से कितना जुटाया गया है?

सतनाम सिंह : वास्तव में यह ऐसा है कि पहले हमने जिसके अनुसार कार्य किया है कि हमने 88 प्रतिशत को खुला रखा है। इस प्रकार जैसा हमने पहले बताया कि हमारी कुल उधारियों में से विदेशी मुद्रा उधारी केवल लगभग 5 प्रतिशत है और पूर्व उधारियों का भुगतान 2014 से शुरू हो रहा है इसलिए हमने उच्चतर प्रतिशत को खुला रखा है। हमने 250 मिलियन को तीन वर्षीय सामूहिक ऋण के रूप में हाल में लिया है और हमने अपनी नीति में परिवर्तन किया है। पहले वर्ष में हम लगभग 15 प्रतिशत को बचाएंगे। इसलिए चूंकि हमने अभी तक उस धनराशि को नहीं लिया है इसलिए मैं आपको केवल भावी नीति के बारे में बता रहा हूं।

मनीष ओस्टवाल : और यह विदेशी ऋण विदेशी परिसम्पत्तियों की ओर जाता है, विशेष रूप से कोयला परिसम्पत्तियों के लिए इसलिए क्या वे परिसम्पत्तियां समान परिसम्पत्ति प्रोविजिनिंग और जोखिम घटक हैं या वे अलग हैं क्योंकि यह एक विद्युत परियोजना नहीं है।

सतनाम सिंह : इस समय में मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता हूं कि क्या कोयला खदान पर भी यही परिपत्र लागू होगा अथवा नहीं परन्तु हम इसका पता लगाएंगे। परन्तु नई परियोजनाओं जिनकी मंजूरी हमने अभी दी है, हेतु संवितरण कुछ समय बाद होगा। इसलिए यह बिलकुल भी चिंता का विषय नहीं है परन्तु फिर भी हम इसका पता लगाएंगे।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न इक्विरस सिक्योरिटीज के देवांग मोदी की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

देवांग मोदी : महोदय, मैं यह समझना चाहता हूं कि हमारे निजी क्षेत्र राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का कितना प्रतिशत कार्यकरण के अधीन है और कितना प्रतिशत पहले से प्रचालनरत है?

सतनाम सिंह : यदि आप हमें ई–मेल भेजें तो हम आपको आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं, हमारे पास ये आंकड़े हैं परन्तु इस समय तत्काल मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

देवांग मोदी : महोदय, मैं केवल विषय विशेष के बारे में जानना चाहता हूं, जो पिछली दो तिमाहियों से चल रहा है हम निरंतर सकल विस्तार देख रहे हैं और संभवतः विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में शेष उद्योग जो पीएफसी जैसे किसी निकाय के इस क्षेत्र में वित्तपोषण के लिए आने और अपनी पंसद की

परियोजनाएं चुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, की उदासीनता के कारण ऐसा हो रहा है। क्या किसी तरह का विषय इस समय चल रहा है और आय के विस्तार का कारण क्या है?

सतनाम सिंह : जी नहीं वास्तव में हमारे पास आदेश की काफी विशाल बही है जिनमें मंजूरी बकाया है और नई मंजूरियों का संवितरण इतनी जल्दी नहीं हो सकता है और हम अपनी पूर्व मंजूरियों के आधार पर ही वितरण कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अन्य लोग ऋण नहीं दे रहे हैं और हम दे रहे हैं। ऐसा केवल अल्पावधिक ऋणों में हो सकता है और हम अल्पावधिक काफी बड़े स्तर पर दे रहे हैं। पहली तिमाही का संवितरण केवल लगभग 75 करोड़ रुपए है।

देवांग मोदी : महोदय, वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2013 की पहली तिमाही के दौरान कितना पुनर्भुगतान किया गया?

सतनाम सिंह : यदि आप समग्र आंकड़े जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कृपया हमें ई–मेल भेजें। हम इसकी जानकारी देंगे। हमारे पास पुनर्भुगतान संबंधी आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं परन्तु मैं आपको बता सकता हूं कि वर्ष 11–12 में हमारी वसूली दर 99.20 प्रतिशत रही थी।

देवांग मोदी : महोदय, आप क्या यह बता सकते हैं कि केवीके एनर्जी ग्रुप और वीडियोकॉन समूह में हमारी भागीदारी कितनी है?

सतनाम सिंह : पहले वीडियोकॉन में हमने उनकी 2 विद्युत परियोजनाओं की दी मंजूरी है और अब हमने 2200 करोड़ रुपए की उनकी गैसफील्ड की मंजूरी दी है। परन्तु विद्युत परियोजनाओं के लिए उन्होंने अभी तक कोई धनराशि नहीं दी है।

देवांग मोदी : ठीक है और गैस के क्षेत्र में उन्होंने कुछ धनराशि निकाली है?

सतनाम सिंह : जी नहीं, हमने इसकी मंजूरी कल ही दी है, अब तक वीडियोकॉन को कोई संवितरण नहीं किया गया है।

देवांग मोदी : और फिर केवीके एनर्जी?

सतनाम सिंह : आप केएसके या केवीके के बारे में बात कर रहे हैं?

देवांग मोदी : महोदय, केवीके। हम जानते हैं कि केएसके सूचीबद्ध है।

सतनाम सिंह : क्या आप मुझे परियोजना के बारे में बता सकते हैं?

देवांग मोदी : केवीके समूह के पास मूल रूप से 2 या 3 अलग परियोजनाएं हैं। मैं समझता हूं केवीके निलाचल और उसके बाद एक सौर परियोजना है और ये सभी चीजे हैं। इसलिए मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मंजूरी की राशि कितनी है और अब तक कितना संवितरण किया गया है?

सतनाम सिंह : केवीके के लिए हमने 1600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

देवांग मोदी : और संवितरण कितना महोदय?

सतनाम सिंह : मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न कोटक के निश्चिंत चवाथे की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

निश्चिंत चवाथे : महोदय, मैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात की ओर देखने का प्रयास कर रहा हूं। पूंजी पर्याप्तता अनुवाद में 16.3 से 18.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुझे आश्चर्य है कि आपने पूर्ववर्ती प्रपत्र जो सभी परियोजनाओं के लिए मूल रूप से 100 प्रतिशत जोखिम घटक रखकर आंका जाता है, में पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना की है तो इसका आंकड़ा कितना होगा।

सतनाम सिंह : 16.67 प्रतिशत।

निश्चिंत चवाथे : उस मामले में यदि मैं पिछले आंकड़े से गणना करूं क्या मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि हमारी समग्र ऋण बही के लगभग 25 प्रतिशत में ऐसी परियोजनाएं हैं जो पहले पूरी हो गई हैं?

सतनाम सिंह : संवितरण की दृष्टि से 25 प्रतिशत से कुछ कम। वास्तव में यह इस तरह से कहना मुश्किल है क्योंकि चालू परियोजनाएं पुनर्भुगतान भी शुरू कर देती हैं। इसलिए बकाया ऋण वस्तुतः शीघ्र ही कम होने लगता है परन्तु अन्यथा यह लगभग 34,000 करोड़ रुपए है, परन्तु सीधे–सीधे हम इस निष्कर्ष पर नहीं आ सकते हैं कि यह 25 प्रतिशत है, क्योंकि 34,000 से समर्थित क्षमता उच्चतर हो सकती है क्योंकि कुछ पुनर्भुगतान हुआ होना चाहिए।

निश्चिंत चवाथे : दूसरा प्रश्न प्रक्रियाधीन ऋण से संबंधित है जिसकी घोषणा आपने कल की है। आपने कहा कि आप लगभग 17,000 करोड़ रुपए की प्रक्रियाधीन ऋण देने की संभावना देखते हैं, यह 5 या 6 राज्यों के लिए है। केवल यह जानना चाहता हूं कि पुर्नगठन पैकेज के साथ राज्य इस दर को किस प्रकार देखते हैं।

सतनाम सिंह : यह ऐसा है कि भारत सरकार बैंकों द्वारा दी गई ऐसी धनराशि जो परियोजना विशिष्ट नहीं है का पुनर्गठन करना चाहती है अब प्रत्येक राज्य ने एक पुनर्गठन पैकेज बनाया है इसका कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को जाता है, कुछ हिस्सा बैंकों को जा रहा है और फिर भी कुछ अंतर है और इस अंतर को भी बांटा जाना है यदि राज्य यह सुनिश्चित करें कि सभी वापसी भुगतान समय पर किये जाते हैं और यह इस प्रयोजनार्थ है कि विद्युत मंत्रालय ने हमें अतिरिक्त सहायता देने के लिए कहा है। हमने इसका उत्तर दिया है कि हमारी समस्त उधारियां परियोजना विशिष्ट हैं इसलिए उस ऋण के पुनर्गठन का कोई प्रश्न नहीं उठता। डिस्कॉम को हमारा अल्पावधिक ऋण काफी कम केवल 1800 करोड़ रुपए है परन्तु फिर भी हम इन डिस्कॉम को अधर में नहीं छोड़ सकते हैं और कहते हैं कि अगर आपको समस्याएं हैं तो हम आपको कोई सहायता नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह हमारा दीर्घावधिक क्षेत्र नहीं है। इसलिए हमने परियोजना नकद अंतर की समस्या से निपटने के लिए उन्हें यह विशेष मानक प्रदान करने की बात सोची है। इन सभी का आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ के बीच है और हम इन्हें 3 वर्ष तक आस्थगन अवधि और 7 वर्ष तक का वापसी भुगतान कार्यकाल उपलब्ध कराने की अनुमति दे रहे हैं। अब इस अवधि में हम महसूस करते हैं कि ऐसी पहलें जो इस समय टैरिफ पुनरीक्षण द्वारा शुरू की जा रही हैं और एपीडीआरपी योजना और अन्य द्वारा पुनर्गठित की गई हैं, से राज्य डिस्कॉम को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और उन्हें कोई समस्या नहीं होगी।

निश्चिंत चवाथे : और महोदय, इन ऋणों की पूर्व शर्तें क्या केन्द्र सरकार द्वारा रखी जाने वाली शर्तों की समान होंगी?

सतनाम सिंह : हमने राज्य सरकार की गारंटी और परिसम्पत्ति ऋण की एक पूर्व शर्त रखी है।

निश्चिंत चवाथे : और मैं समझता हूं कि कुछ पूर्व शर्तें जिन पर पूर्व हमने चर्चा की है, अवधिक आधार पर लेखों का प्रकटन करने और अन्य बातों के बारे में हैं। क्या ये सभी चीजें इसी प्रकार की हैं.....

सतनाम सिंह : वे शर्तें भी इसमें होंगी।

संचालक : हमारा अगला प्रश्न स्पार्क कैपिटल के गणेश राम की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

गणेश राम : मैं गणेश राम हूं। मुझे दो प्रश्न पूछने हैं। एक यह की आप कोल इण्डिया की बोर्ड बैठक का उल्लेख कर रहे थे। मैं यह सोच रहा था कि कोला पूलिंग जिसके बारे में बैठक में निर्णय नहीं लिया गया, के कार्यान्वयन की पद्धति के संबंध में आपकी प्रत्याशा क्या है। क्या आपको एसईबी के साथ इस पर चर्चा करने का मौका मिला है। वे महंगी विद्युत के लिए भुगतान करने में सक्षम होंगे। लगभग सभी पीपीए को बदला जाना चाहिए। इस बारे में आपकी राय क्या है?

सतनाम सिंह : अनेक क्षमताएं जो बनाई गई हैं सरकार द्वारा दिये गये इस आश्वासन पर आधारित हैं कि कोयला उपलब्ध कराया जायेगा और कोल इण्डिया से इसे उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। तत्पश्चात यदि कोल इण्डिया लिंकेज के अनुसार कोयला उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगा तो विकासकर्ता की कोई गलती नहीं होगी। यदि कोल इण्डिया लिंकेज आधारित कोयला उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होता है तो कोल इण्डिया को केन्द्र सरकार द्वारा आयात करने और जरूरत को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। यदि कोल इण्डिया इसका आयात करता है तो वह अतिरिक्त कीमत की मांग करेगा और वह उस कीमत का प्रयोग कोयले की पूलिंग के लिए किया जायेगा जिसे राज्य वितरण कम्पनियों पर प्रभारित किया जायेगा। हमने प्रत्यक्ष रूप से कोई बातचीत नहीं की है परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भूमिका होगी।

गणेश राम : परन्तु क्या आप शीघ्र होने वाली कोल इण्डिया की अगली बैठक में कोल पूलिंग के किसी भी समय वास्तविकता में बदलने की उच्च संभावना को नहीं देखते हैं, जो अगले महीने या इसके बाद हो सकता है?

सतनाम सिंह : निस्संदेह हमें उनके साथ इसकी जांच करनी होगी। विकासकर्ता निश्चित रूप से ऐसा होने की आशा करते हैं।

गणेश राम : मेरा दूसरा प्रश्न इस बात को देखते हुए परियोजना चलाने के संबंध में बैंकों से ऋण लेने की आपकी सोच से संबंधित है कि आपके पास 50 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता, 50 प्रतिशत जोखिम है और इससे आपका जोखिम संबंधी पहलू भी कुछ हद तक कम होता है। इस प्रकार क्या आपके दिमाग में कोई विकास संबंधी कार्यनीति चल रही है?

सतनाम सिंह : यह परिपत्र बिलकुल हाल का है और हमने सबसे पहले हमारी पूंजी पर्याप्तता पर इसके प्रभाव की गणना की है। आपके सुझाव के अनुसार हमें यह देखना होगा कि क्या वहां व्यापार करने की कोई संभावना है।

गणेश राम : अंततः, क्या आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ इस संबंध में चर्चा करने का मौका मिला है या वे इस कारण से सीएआर की ओर अधिक देख रहे हैं क्योंकि वे आपके पास एएए को देखते हुए एनबीएफसी और अधिक बुनियादी तौर पर इनफ्रा एनबीएफसी के लिए पूंजी पर्याप्तता से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। क्या अब वे लाभ उठाने की बजाय पूंजी पर्याप्तता अनुपात की ओर ध्यान देने की इच्छा रखते हैं?

सतनाम सिंह : दोनों एक ही बात दर्शाते हैं चाहे आप इसे लाभ उठाना कहें या पूंजी पर्याप्तता कहें। मैं नहीं समझता कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अपना खाका बदलना होगा, चाहे वह लाभ उठाना हो या पूंजी पर्याप्तता हो।

गणेश राम : परन्तु लाभ उठाने में 100 प्रतिशत जोखिम देखा जाता है क्योंकि वे ऋण – इक्विटी की ओर देखते हैं और यदि आपके पास 50 प्रतिशत जोखिम घटक है तो आपका सीएआर काफी बेहतर दिखाई देगा और इसका काफी अधिक लाभ उठा पायेंगे और अपने आरओई में सुधार कर सकेंगे। मैं केवल इसी दृष्टि से देख रहा हूं।

सतनाम सिंह : जी नहीं, ऐसे किसी संस्थान जहां कतिपय विशिष्ट परिसम्पत्ति के लिए जोखिम का घटक कम होता है वहां 100 प्रतिशत जोखिम घटक की आधार की बजाय तद्नुसार लाभ की गणना की जाएगी।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न यूटीआई म्युचुअल फण्ड से अमित प्रेमचन्दानी की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

अमित प्रेमचन्दानी : इस तिमाही में आपकी परिसम्पत्ति को कितना रिप्राइस किया गया है। क्योंकि ऋणों पर आय में भारी वृद्धि हुई है।

सतनाम सिंह : 17,900 करोड़ रुपए।

अमित प्रेमचन्दानी : महोदय, क्या आपकी राय में इस तरह का मार्जन निरंतर रहेगा या केवल कुछ समय के लिए है?

सतनाम सिंह : पहले भी मैंने अपने निवेशकों को यह बताया है कि हमारा मार्जिन दबाव में केवल इसलिए आया था कि आरबीआई निरंतर ब्याज बढ़ा रहा था और हमने वर्ष–वार आधार पर अपनी परिसम्पत्ति का पुनर्गठन और देयता का पुनर्गठन उसके समतुल्य किया है चूंकि देयता में बार–बार बदलाव किया जा रहा था इसलिए हम परिसम्पत्ति के पुनर्गठन में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। अब क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दर में वृद्धि को रोक दिया है हमारे मार्जिन और विस्तार सामान्य स्तर पर पहुंच गए हैं और मुझे आशा है कि ऐसा जारी रहेगा।

अमित प्रेमचन्दानी : महोदय, अगली 3 तिमाही के दौरान परिसम्पत्तियों को कितना रिप्राइस किया जायेगा?

सतनाम सिंह : यह लगभग 20,000 करोड़ रुपए होगा।

अमित प्रेमचन्दानी : और क्या यह वर्तमान ऋण दर जिस पर ये हैं, से उच्च स्तर पर होगा?

सतनाम सिंह : यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन तारीखों को ब्याज दर क्या रहती है। आज की तारीख के अनुसार यह उच्चतर है यदि रिजर्व बैंक कल ब्याज दरें घटा देता है और उसके बाद हमें अपनी ब्याज दर में संशोधन करना पड़ता है तो इसके कारण इसमें मामूली कमी आयेगी परन्तु अन्यथा यह उच्चतर होने वाली है।

अमित प्रेमचन्दानी : और महोदय, क्या आरबीआई द्वारा दरें घटाये जाने बाद पिछले 6 महीने के दौरान आपने दरों में कटौती की है?

सतनाम सिंह : जी नहीं।

संचालक : हमारा अगला प्रश्न गोल्डमैन साक्स के राहुल जैन की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

राहुल जैन : केवल दो प्रश्न हैं। पहला इस एसईबी के संबंध में है, हमने इस तिमाही में एसईबी को कितना उधार दिया है और एसईबी को आगे कितना उधार दिये जाने की संभावना है जो पुनर्गठन या प्रक्रियाधीन एसईबी का हिस्सा होगा?

सतनाम सिंह : इस तरह के विशेष प्रश्न का हम केवल तभी उत्तर दे सकते हैं जब आप हमें मेल भेजें परन्तु एसईबी को समग्र कितना दिया गया है वो मैं आपको बता सकता हूं। यह लगभग 7,700 करोड़ रुपए है। मैं समझता हूं आप 6 राज्यों के बारे में पूछ रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है?

राहुल जैन : जी नहीं, पहला हिस्सा इस तिमाही में एसईबी को कुल मिलाकर कितना उधार दिया गया है?

सतनाम सिंह : मैंने इसी का उत्तर दिया है। आप इन 6 राज्यों का संदर्भ दे रहे हैं ना?

राहुल जैन : उन 6 राज्यों का जिनके बारे में आपने बात की।

सतनाम सिंह : कृपया हमें ई–मेल भेजें हम इसका उत्तर देंगे।

राहुल जैन : दूसरी बात यह सर, आपने जीवीके विदेशी मुद्रा ऋण के बारे में बात की, केवल यह जानना चाहता हूं क्या यह जीवीके को विदेशी मुद्रा में नई उधारी है या किसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक से एक प्रकार का बाईआउट है?

सतनाम सिंह : वास्तव में अग्रणीय बैंक ने पूरे ऋण की जिम्मेवारी ली है और वे इसे आगे बेच रहे हैं। इसलिये यह एक प्रकार का बाईआउट नहीं है बल्कि इसकी बाद में बिक्री की जा रही है।

राहुल जैन : हमने कितना खरीदा है। यदि मैंने सही सुना तो क्या यह 200 मिलियन तक है।

सतनाम सिंह : 135 मिलियन डॉलर। मुझे यह अभी तक नहीं मिला है कल हमने इसकी मंजूरी दे दी है, तत्पश्चात वे इसकी शर्तों को पूरा करेंगे और इसके बाद संभवतः हम इस पर चर्चा करेंगे।

राहुल जैन : और महोदय, केवल एक और बात। हमारी ऋण बही या उन विद्युत परियोजनाओं जिनमें हमारी भागीदारी है, में सीओडी या पुनर्भुगतान के लिए कितनी राशि अगले 12 महीनों में लाई जा रही है, इसमें से कुल बही का 11.5 प्रतिशत जो हमें मिला है, कितना है?

सतनाम सिंह : क्षमता के संबंध में विवरण हमारे पास अभी नहीं हैं। कृपया हमें ई–मेल करें, हम आपको बताएंगे।

संचालक : हमारा अगला प्रश्न मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के उमंग शाह की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

उमंग शाह : मेरे अधिकांश प्रश्नों का जवाब दिया जा चुका है केवल एक प्रश्न क्या आप आरबीआई के उस परिपत्र पर कुछ प्रकाश डालेंगे, जिसका आपने आईएफसी के लिए संदर्भ दिया जिसमें आरबीआई ने आपसे नहीं ली गई सीमाओं पर 50 प्रतिशत तक से अधिक राशि उपलब्ध कराने के लिए कहा है, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं?

सतनाम सिंह : देखिये, जब हम किसी विद्युत परियोजना के लिए ऋण की मंजूरी देते हैं तो वह मंजूरी निर्माण की सम्पूर्ण अवधि के लिए होती है। हम वर्ष–वार आधार पर ऋण की मंजूरी नहीं देते हैं। अगले वर्ष हम 10 प्रतिशत का निर्माण करने जा रहे हैं। हम 10 प्रतिशत ऋण लेते हैं, उससे अगले वर्ष 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत ऋण लेते हैं। इस प्रकार यह एकबारगी मंजूरी होती है जिसका उपयोग अगले 3–4 वर्षों की अवधि में करना होता है। आरबीआई इस परिपत्र के अनुसार यह कह रहा है कि जो कुछ भी वचनबद्ध हो और इस पर किया गया हो यह आशा की जाती है कि आईएफसी पूंजी अग्रिम रूप में उपलब्ध करायेगा जब भी किसी भी तरह से वे धनराशि लेते हैं जो आगे ऋण परिसम्पत्ति बन जाती है और हमारे पास संगत पूंजी होनी चाहिए। परन्तु जब तक वह नहीं ली जाती है तब भी रिजर्व बैंक के परिपत्र में उल्लेख है कि आईएफसी के पास अपेक्षित पूंजी का 50 प्रतिशत होना चाहिए। अब इसका यह अर्थ होगा कि हमारे जैसी संस्था जिसकी बकाया मंजूरी बहुत अधिक लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए है, के लिए हमें काफी भारी मात्रा में पूंजी उपलब्ध करानी होगी और जिससे पूरा क्षेत्र अव्यवहार्य हो जायेगा क्योंकि उच्च पूंजी का अर्थ उच्च लागत है और उच्चतर उधारी दर है। इस प्रकार हमने इस बात पर भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान दिलाया है कि विद्युत क्षेत्र में यह करने योग्य नहीं है।

संचालक : हमारा अगला प्रश्न आईसीआईसीआई डायरेक्ट की काजल गांधी की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

काजल गांधी : मैं यह जानना चाहती हूं कि इस तिमाही में इतनी अधिक आय होने के कारण क्या हैं?

सतनाम सिंह : आय इसलिए अधिक है क्योंकि 17,900 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियों का पुनर्गठन किया गया है और 15,000 करोड़ रुपए पिछली तिमाही में हमने संवितरित किए हैं, जिनमें उच्चतर दर पर उधारी की कुल आय पहली तिमाही में प्राप्त हुई है।

काजल गांधी : और सततगामी एनआईएम कितनी होगी जो आगे आएगी?

सतनाम सिंह : यह सततगामी स्तर है, बशर्ते कि आरबीआई ब्याज दरों के साथ बार–बार छेड़छाड़ न करे।

काजल गांधी : तो हम लगभग 4 प्रतिशत के स्तर पर हैं।

सतनाम सिंह : जी हां।

संचालक : हमारा अगला प्रश्न जीईईसीईई इनवेस्टमेंट से मिथुन सोनी की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

मिथुन सोनी : महोदय, आपने उल्लेख किया कि हमारी कुल बही जो हमारे पास है लगभग 34,000 करोड़ रुपए की परियोजना है जो पहले से पूरी हो गई। क्या मैं सही हूं?

सतनाम सिंह : जी हां.।

मिथुन सोनी : और वित्त वर्ष 2013 के दौरान 39,000 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पूरा किया जायेगा।

सतनाम सिंह : वह सही है। परन्तु यह 39,000 हजार करोड़ वास्तव में वित्तीय आंकड़ा है जो संगत क्षमता नहीं बताता है क्योंकि जब परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो वापसी भुगतान शुरू होता है। इसलिए 34 और 39 को जोड़ा नहीं जा सकता है और यह संगठन पर भी निर्भर करता है। आप निजी क्षेत्र या राज्य क्षेत्र को कितना उधार दे रहे हैं? इससे भी क्षमता का गठन परिवर्तित हो जायेगा परन्तु क्षमता ही महत्वपूर्ण है। इन वित्तीय आंकड़ों से कितनी क्षमता सृजित होगी, हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं।

मिथुन सोनी : मैं सहमत हूं महोदय, और महोदय, वित्त वर्ष 2013 में किस तरह की परियोजनाओं को पूरा किया जायेगा। क्या आप कोई आंकड़ा बता सकते हैं?

सतनाम सिंह : मैं आपको मोटे तौर पर प्रतिशत बता सकता हूं। 39,000 करोड़ रुपए में से कोयला आधारित लगभग 33,000 है, गैस आधारित 44,00, जल विद्युत 972, नवीकरणीय 662 करोड़ रुपए के हैं।

मिथुन सोनी : और महोदय वित्त वर्ष 2014 में उन परियोजनाओं के लिए आपके कुल मूल्यानुसार अनुमानित आंकड़े क्या हैं, जिनके पूरा होने की संभावना है?

सतनाम सिंह : अभी की स्थिति के अनुसार ये लगभग 17,600 हैं।

मिथुन सोनी : वित्त वर्ष 14 के लिए?

सतनाम सिंह : जी हां, परन्तु होता क्या है कि परियोजनाएं जो पूरी होने वाली होती है उनके लिए संवितरण हो जायेगा और उसे भी जोड़ दिया जायेगा।

मिथुन सोनी : और महोदय, देयता की दृष्टि से आप इस वर्ष राशि के अनुसार और दरों के अनुसार किस तरह की रिप्राईसिंग की आशा करते हैं?

सतनाम सिंह : राशि पुनर्गठन देयता की दृष्टि से मैं समझता हूं ये लगभग 24,700 करोड़ रुपए हैं।

मिथुन सोनी : इस प्रकार कुल ऋण बही में से 24,700 की कुल उधारी को रिप्राईस किया जायेगा और उस दर की लागत वृद्धि कितनी होगी जिस पर इसका पुनर्गठन किया जाना है?

सतनाम सिंह : लागत वृद्धि के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूं। परन्तु हमारी परिवर्तनशील दर पर देयता 24,700 रिप्राईसिंग के लिए आ रही है परन्तु कुल परिवर्तनशील देयता लगभग 29,000 हजार करोड़ रुपए की है और ये अलग–अलग ब्याज दर पर है। कुछ 9000 करोड़ रुपए मूल दर पर, 1800 करोड़ रुपए पीएलआर आधारित दर पर, 2500 सामान्य दर पुनर्गठन पर, 8600 करोड़ रुपए एक वर्ष के पुनर्गठन बॉण्ड पर और 1200 करोड़ रुपए तीन वर्षीय पुनर्गठन बॉण्ड के साथ और 4207 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में हैं।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न निर्मल बैंग से नीतिन अरोड़ा की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

नीतिन अरोड़ा : महोदय, क्या हम ये जान सकते हैं कि मान लीजिए विद्युत मंत्रालय ने अब 12वीं योजना में 88 जीडब्ल्यू को अनुमोदित किया है तो मैं समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु अनंतिम अनुमान हो सकता है कि 12वी योजना में पूरा किया जाने वाला इस 88

जीडब्ल्यू के संबंध में क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोयला और गैस तथा जल विद्युत की दृष्टि से हमारा हिस्सा कितना होगा?

सतनाम सिंह : कोयला, गैस और जल विद्युत मैं आपको यह नहीं बता सकूंगा परन्तु उसके मूल्य के अनुसार कम से कम 20 प्रतिशत प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है।

नीतिन अरोड़ा : महोदय, मूल्य के अनुसार जैसा आप कह रहे हैं उस 20 प्रतिशत का कोई हिस्सा, किसी प्रकार की देरी या और कोई बात जिसकी वजह से कोयला और गैस संबंधी कोई समस्या, कोई परियोजना विशेष, जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, जो समस्या का सामना कर रहे हैं और आपने हमें बताया कि कोनासीमा ऐसी एक परियोजना है परन्तु वह एनपीए है परन्तु नई क्षमताएं बनाई जा रही हैं।

सतनाम सिंह : नई क्षमताएं जो रिलायंस की समलकोट में हैं। हम इन परियोजनाओं के बारे में आपको नहीं बता पाएंगे जो वित्तपोषण के लिए हमारे पास नहीं आए हैं। समलकोट हमारे पास वित्तपोषण के लिए आया था हमने बैंक गारंटी के साथ उसे मंजूरी दी जो उन्हें स्वीकार नहीं है। वहां गैस की उपलब्धता में देरी हो सकती है। शेष परियोजनाएं हमारे पास नहीं आई हैं इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जहां तक कोयले का संबंध है चूंकि कोल इण्डिया ने कल की बोर्ड की बैठक में कीमत निर्धारण के बारे में पहले ही निर्णय ले लिया है इसलिए मैं नहीं समझता कि भविष्य में कोयले की कोई खास समस्या होगी। सभी परियोजनाओं को यदि अधिक नहीं तो कम से कम 65 प्रतिशत तक कोयला मिलेगा।

नीतिन अरोड़ा : महोदय, मेरा अगला प्रश्न यह होगा कि आपने ऋणों के पुनर्गठन की बात की है। मैं इसे पुनर्गठन नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप इन एसईबी जिन्हें आप 6 राज्य कह रहे हैं, को 3000 से 5000 हजार करोड़ रुपए का ऋण देंगे। इस बार में मेरी राय है कि वर्तमान विषय यह है कि हम देख रहे हैं कि आप जानते हैं 50 प्रतिशत की कमी राज्य द्वारा ली जायेगी और तत्पश्चात कुल एसईबी ऋण बैंक के लोगों द्वारा लिया जायेगा। इसलिए आपकी राय में प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम प्रतिशत हिस्सा कितना होगा। मैं मानता हूं कि हम एसईबी के बारे में बहुत कम जानते हैं।

सतनाम सिंह : केवल तभी जब मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव को अनुमोदित करता है, इस पर टिप्पणी करना सही होगा। तब तक हमारे पास केवल प्रारूप है और इसलिए मैं नहीं समझता कि मुझे इस पर टिप्पणी करनी चाहिए।

नीतिन अरोड़ा : परन्तु मान लीजिए एसईबी में हमारा लगभग 5000 करोड़ रुपए का ऋण है, यदि सरकार उसका पुनर्गठन करने को कहती है जैसा कि आपने कहा कि यदि केन्द्र कोयला पूल कीमत निर्धारण के लिए कहता है क्योंकि यह होना चाहिए तो क्या इसी प्रकार से मैं यह मान सकता हूं कि केन्द्र हमें भी यह कह सकता है कि हमें भी ऐसा करना पड़ेगा।

सतनाम सिंह : जी नहीं, हम उसका हिस्सा नहीं हैं।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न क्वेनटम एएमसी से अतुल कुमार की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

अतुल कुमार : कोनासीमा और श्री महेश्वर जैसे पिछले वर्ष होने वाले अधिकांश मामलों में जैसा हमने देखा, उसे छोड़कर परिसम्पत्तियों का एनपीए में जाना, जिसे आप सन्निकट देखते है तथा कोई अन्य परिसम्पत्ति जो एनपीए में जा सकती है?

सतनाम सिंह : बिलकुल नहीं। अभी की स्थिति के अनुसार ऐसा कोई संकेत नहीं है।

अतुल कुमार : अपनी आरंभिक टिप्पणियों में आपने एसईबी पुनर्गठन की बात की और बाद में एक प्रश्न में आपने एसईबी को विशेष ऋण देने के बारे में भी कहा। इस प्रकार क्या ये दोनों अलग हैं या जब आपने यह दोनों बातें कहीं तो आप एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे।

सतनाम सिंह : एसईबी पुनर्गठन, डिस्कॉम ऋण पुनर्गठन जैसा मैंने कहा विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और बैंकों द्वारा किया जा रहा है। जो सहायता हम दे रहे हैं वह एक अलग संरचना है। प्रक्रियाधीन ऋण है, विशेष प्रकार के ऋण है, जिससे कि उन्हें नकद अंतर से उबरने में मदद मिल सके। इस प्रकार दोनों अलग–अलग हैं।

अतुल कुमार : तो पुनर्गठन की दृष्टि से आप हिस्सा नहीं लेंगे। आप केवल ऋण देने का कार्य कर रहे हैं?

सतनाम सिंह : हां ये बिलकुल सही है।

अतुल कुमार : और इन विशेष ऋणों पर जैसा कि अतिरिक्त प्रावधानों आदि जैसे पुनर्गठन के मामले में हमें जानकारी है उन्हें किया गया है, इस प्रकार आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आवश्यकता को आप इन विशेष ऋणों द्वारा भी पूरा करेंगे या यह सामान्य ऋण का कोई अन्य प्रकार होगा।

सतनाम सिंह : यह एक नया ऋण है और प्रोविजनिंग का कोई प्रश्न नहीं है।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न टौरस म्युचुअल फण्ड की मनीषा पोरवाल की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

मनीषा पोरवाल : पिछले प्रश्न से एसएबी को प्रक्रियाधीन ऋणों के इस मामले में मैं यह जानना चाहती हूं कि आगामी तिमाहियों में ऐसे कितने और ऋण दिये जा सकते हैं क्योंकि मैं समझती हूं कि इन एसईबी पर ऐसी समयावधियों में जो थोड़ी लंबी हो सकती हैं इस प्रकार का दबाव बना रहेगा, तो पीएफसी इन्हें कितनी सहायता दे सकता है?

सतनाम सिंह : यह कोई आवधिक प्रक्रिया नहीं है। यह बैंकों द्वारा की जा रही एकबारगी प्रक्रिया है और शेष अंतर को पीएफसी और आरईसी द्वारा पाटा जा रहा है। इसलिए इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न क्राइसिल के ओंकार कुलकर्णी की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

ओंकार कुलकर्णी : मैं उस पूरी धनराशि के बारे में जानना चाहता हूं जिसके लिए आपने लगभग 17,000 करोड़ रुपए के प्रक्रियाधीन ऋण का उल्लेख किया है, क्या यह सही है?

सतनामसिंह : जीहां।

ओंकारकुलकर्णी : इन पर लगाई जाने वाली ब्याज दर कितनी होगी। क्या कोई विशेष ब्याज दर होगी क्या हमारे मौजूदा ऋणों के समान ही होगी?

सतनाम सिंह : सामान्य ब्याज दर।

ओंकार कुलकर्णी : और इन ऋणों का वितरण किसी अवधि के दौरान होगा या यह एकबारगी प्रकार का ऋण होगा।

सतनाम सिंह : राज्य डिस्कॉम की जरूरत के आधार पर होगा।

ओंकार कुलकर्णी : और महोदय, विदेशी मुद्रा ऋणों के बारे में एक बार वित्त वर्ष 2014 में पुनर्भुगतान के लिए कौन से ऋण आने वाले हैं?

सतनाम सिंह : आपका मतलब है कितने।

ओंकार कुलकर्णी : धनराशि कितनी होगी। करोड़ रुपए में या डॉलर में?

सतनाम सिंह : लगभग 250 करोड़ रुपए।

ओंकार कुलकर्णी : और महोदय, अंततः वितरण की ओर, वितरण से ट्रासंमिशन और वितरण क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष आधार पर गिरावट आई है तो क्या इस संबंध में कुछ किया गया है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तिमाही के दौरान कोई वितरण निर्धारित नहीं है।

सतनाम सिंह : ट्रांसमिशन के लिए पहली तिमाही में यह लगभग 286 करोड़ रुपए है। यह केवल लगभग 4 प्रतिशत है और वितरण के लिए 336 करोड़ रुपए है जो लगभग 4 प्रतिशत है और हमारे सभी संवितरण, संवितरण अनुसूची के अनुसार हैं।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न ऑलमंड्ज ग्लोबल के मंगेश कुलकर्णी की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

मंगेश कुलकर्णी : मैं इस प्रक्रियाधीन वित्त के बारे में जानना चाहता हूं। इसमें आरईसी का योगदान क्या होगा?

सतनाम सिंह : उसी प्रकार का।

मंगेश कुलकर्णी : विदेशी मुद्रा के ऋण के 6259 करोड़ रुपए का अलग–अलग ब्यौरा?

सतनाम सिंह : आप किस तरह का अलग–अलग ब्यौरा चाहते हैं।

मंगेश कुलकर्णी : मुद्राओं में।

सतनाम सिंह : बकाया डॉलर 540 मिलियन डॉलर है। 24 मिलियन यूरो और जापानी येन (जेपीवाई) 41643 है।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न एवेडस सिक्योरिटीज के जैनी शाह की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

जैनी शाह : जानना चाहता हूं कि एसईबी के लिए तैयार किये जा रहे पुनर्गठन पैकेजों की स्थिति का ब्यौरा क्या है। ऐसी कुछ समाचार रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, इस पर वित्त मंत्रालय द्वारा इस समय विचार किया जा रहा है परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में अनुमोदन प्रदान किया है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है?

सतनाम सिंह : हम इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं क्योंकि हमारा ऋण इसका कोई हिस्सा नहीं है परन्तु उस प्रक्रिया में मेरा केवल अनुमान है कि जहां राज्य सरकारें पुनर्गठन प्रवृत्ति पर सहमत हो गई हैं उन प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न एमबिट कैपिटल के पंकज अग्रवाल की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

पंकज अग्रवाल : यदि मैं डिस्कॉम द्वारा अल्पावधिक ऋण की राशि को देखता हूं तो यह लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक है। इसलिए केवल ये जानना चाहता हूं कि वे अल्पावधिक ऋण का कैसे उपयोग कर रहे हैं। मेरा मतलब है इस अल्पावधिक ऋण के प्रयोग क्या हैं?

सतनाम सिंह : मैं नहीं समझता मैं इस पर टिप्पणी कर सकता हूं परन्तु मेरा अनुमान है कि इनका उपयोग नकद अंतर को भरने के लिए किया जा रहा है।

पंकज अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह था कि यदि नकद प्रवाह प्रचालनों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो यदि हम उन्हें दीर्घावधिक ऋण भी देते हैं, परियोजनाएं विशिष्ट ऋण देते हैं, मेरा मतलब है यदि उनके पास नकद नहीं है तो वे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वे आपको दीर्घावधिक ऋणों का भी भुगतान कर दें।

सतनाम सिंह : यही कारण है कि हम प्रत्येक राज्य विद्युत सुविधा के साथ त्रिपक्षीय करार में शामिल हुए हैं। जहां पहली आय एक अलग खाते में चिन्हित की गई है। हम उससे पैसा नहीं निकालते हैं परन्तु यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो हम उस खाते को बंद कर सकते हैं और इस पर मासिक आधार पर निगरानी रखी जा सकती है।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न एशियन मार्किट से कमलेश कोटक की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

कमलेश कोटक : महोदय, आपने कहा विशेष वित्त जिसे एसईडी के लिए मंजूर किया जा रहा है, मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या यह इस तिमाही के लिए पहले ही हमारी मंजूरियों का हिस्सा है।

सतनाम सिंह : जी नहीं।

कमलेश कोटक : इसका मतलब यह अगली तिमाही में आयेगा। क्या यह सही है?

सतनाम सिंह : हमने कल ही यह प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा है।

कमलेश कोटक : महोदय, तब भी यदि मैं हमारी मंजूरियों की ओर देखता हूं इनमें वर्ष दर वर्ष तेजी से गिरावट आई है। इस प्रकार मांग में कुछ कमी आई है और हम अब एसईबी की ओर विशेष रूप से अधिक सख्त हो गए हैं जिनमें काफी गिरावट प्रदर्शित हुई है।

सतनाम सिंह : जी नहीं, यह इसलिए है क्योंकि राज्य क्षेत्र से निजी क्षेत्र को वृद्धिशील पूंजी अभिवृद्धि की दृष्टि से परिवर्तन हो रहा है जैसा आप जानते हैं 11वीं योजना में निजी क्षेत्र का योगदान लगभग एक तिहाई था और 12वीं योजना में इसके लगभग 60 प्रतिशत होने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार निजी क्षेत्र के मामले में हमें आरबीआई के ऋण देने संबंधी विवेकशील मानकों का पालन करना होगा और ऋण की राशि उस राशि से काफी कम होगी जिसे हम केन्द्र या राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उधार दे सकते हैं। इसी कारण से यदि आप समान संख्या में परियोजनाएं चलाते हैं तो भी निजी क्षेत्र के मामले में हमारे ऋण कम होंगे चूंकि आगे निजी क्षेत्र की वृद्धिशील प्रतिशत कम होगी। इसी वजह से हमारी मंजूरियों में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है।

कमलेश कोटक : तो यही प्रवृत्ति महोदय, आने वाली तिमाही में भी जारी रहेगी, मंजूरियों में कुछ कमी आएगी?

सतनाम सिंह : जी नहीं।

कमलेश कोटक : समग्र रूप से क्योंकि समग्र आंकड़े में भी गिरावट आ गई है।

सतनाम सिंह : तिमाही के लिए मैं नहीं कह सकता परन्तु वर्ष के दौरान यही प्रवृत्ति रह सकती है।

कमलेश कोटक : और महोदय, एपीडीआरपी की मंजूरियों का क्या होगा। क्या यह तिमाही के दौरान मंजूरियों की वजह से है या इसलिए है कि 12वीं योजना में इसके बारे में एक नया परिप्रेक्ष्य अपनाया गया है।

सतनाम सिंह : पहली तिमाही में कोई मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि हमने अधिकांश मंजूरी पहले ही दे दी है और केवल 1000 करोड़ रुपए बचे हैं, जिन्हें दूसरी तिमाही में हमें मंजूर करना है। इस प्रकार ये धनराशि लगभग समाप्त है।

कमलेश कोटक : और महोदय, वसूली की ओर आते हुए मैंने पिछले वर्ष की गणना की है। हमने पिछले वर्ष में वसूली वित्त वर्ष 12 के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी पिछड़ती हुई देखी है। हमारी ऋण बही में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारी वसूली 25 प्रतिशत तक घट गई है। इस प्रकार क्या ऐसा कोई दबाव वापसी भुगतान की ओर बन रहा है, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं?

सतनाम सिंह : जी नहीं, वापसी भुगतान की तरफ इस समय कोई दबाव नहीं है। यदि सरकार द्वारा किये जा रहे सभी उपायों का आगे कोई लाभ नहीं होता है तब भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है परन्तु भविष्य में हम पहले से सभी स्तरों पर लिये गये निर्णयों के कारण ऐसी कोई संभावना नहीं देखते हैं।

कमलेश कोटक : परन्तु महोदय, आंकड़े दर्शाते हैं कि तिमाही वसूली दर और वर्ष–वार वसूली दर में तेजी से गिरावट आई है।

सतनाम सिंह : होता यह है कि कभी–कभी कुछ सुविधाएं समय पर भुगतान नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि वसूली दर बिल्कुल अलग दिखाई देती है परन्तु हमारे पिछले अनेक वर्षों का अनुभव यह रहा है कि थोड़ी–बहुत देरी होती है और तत्पश्चात भुगतान हो जाता है।

कमलेश कोटक : तो आप इस संदर्भ में चिंता की कोई बात नहीं देखते हैं?

सतनाम सिंह : जी नहीं।

कमलेश कोटक : और महोदय, एक प्रस्ताव में जैसा मैं पुनर्गठन के बारे में मानता हूं 2 वर्ष की आस्थगन अवधि की स्थिति है। क्या इससे हमारे वसूली चक्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा?

सतनाम सिंह : जी नहीं। आस्थगन से नकारात्मक प्रभाव के बजाय वसूली करने में मदद मिलेगी। यदि पुनर्गठन पैकेज या अतिरिक्त ऋण जिन्हें हम देते हैं, पर 3 वर्ष की आस्थगन अवधि की अनुमति दी जाती है, तो इससे ब्याज की वसूली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मूल धन के भुगतान में कुछ अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। इस प्रकार उस वर्ष और अधिक नकद प्रवाह होगा।

कमलेश कोटक : उन राज्यों जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, में से वे प्रमुख राज्य कौन से हैं जहां एसईबी के हिस्से के रूप में हमारी मंजूरियां और वितरण सर्वाधिक रहे हैं?

सतनाम सिंह : ऋण बही मेरे पास तत्काल उपलब्ध है। आपका मतलब पहली तिमाही में संवितरण से है।

कमलेश कोटक : जी हां।

सतनाम सिंह : महाराष्ट्र, राजस्थान, कुछ हद तक मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश और अन्य निजी क्षेत्र की परियोजना है।

कमलेश कोटक : महोदय अंत में आपने उल्लेख किया कि मंजूरियां परियोजना विशिष्ट हैं इसलिए विशेष रूप से किसी परियोजना विशेष का संवितरण 3–4 वर्ष की समयावधि के लिए होगा?

सतनाम सिंह : जी हां। कोयला आधारित स्टेशन लगभग 4 वर्ष के लिए है।

कमलेश कोटक : और वापसी भुगतान पूरा होने के बाद 1 या 2 वर्ष की आस्थगन अवधि के बाद शुरू हो जायेगा।

सतनाम सिंह : पूरा होने के 6 महीने में, पहला वापसी भुगतान सर्वोत्तम रूप से 9 महीने की आस्थगन अवधि में।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न आईसीआईसीआई सेक्शन के अभिशेख मुरारका की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

अभिशेख मुरारका : केवल दो प्रश्न, पहला आपके विदेशी मुद्रा ऋणों के बारे में, विदेशी मुद्रा की अवशिष्ट अधिकांशतः क्या होगी?

सतनाम सिंह : 4 वर्ष से थोड़ी कम।

अभिशेख मुरारका : तो यह कम हुई है। क्योंकि 2 तिमाही पहले या पिछली तिमाही से पहले मैं समझता हूं यह लगभग 4.5 वर्ष थी।

सतनाम सिंह : जी हां।

अभिशेख मुरारका : और दूसरी बात यह महोदय, कि मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिये। आपने कहा कि आपने एक नई नीति बनाई है कि आप 15 प्रतिशत जुटाएंगे। वह 15 प्रतिशत था या 50 प्रतिशत?

सतनाम सिंह : पहले वर्ष में 15 प्रतिशत।

अभिशेख मुरारका : और महोदय, अंत में यह एक प्रकार से दोहराना होगा परन्तु आप बता रहे थे कि वित्त वर्ष 13 में लगभग 39,000 हजार मेगावाट।

सतनाम सिंह : मेगावाट नहीं वह करोड़ है।

अभिशेख मुरारका : और जो ब्यौरा आपने दिया वह भी करोड़ में था। अर्थात जिसे पूरा किया जाना है।

सतनाम सिंह : जी हां।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न वीईसी इन्वेस्टमेंट्स के राहुल अग्रवाल की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

राहुल अग्रवाल : मेरा केवल एक प्रश्न है। यदि मेरी समझ ठीक है तो आपने कहा कि 6 राज्य डिस्कॉम हैं जिनमें हमारे 5800 करोड़ रुपए के दीर्घावधिक ऋण हैं और 1890 करोड़ रुपए के अल्पावधिक ऋण हैं, यह परियोजना विशिष्ट नहीं है?

सतनाम सिंह : ये परियोजना विशिष्ट हैं।

राहुल अग्रवाल : तो इनके लिए क्या कोई रिप्राईसिंग की जानी है?

सतनाम सिंह : जी नहीं, यहां हम यह कह रहे हैं कि हम इन ऋणों का पुनर्गठन नहीं कर रहे हैं और हम अपनी प्राप्तियां निर्धारित तारीखों को चाहते हैं।

राहुल अग्रवाल : इस प्रकार इन ऋणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा?

सतनाम सिंह : कोई परिवर्तन नहीं होगा।

राहुल अग्रवाल : इस प्रकार मूलतः ये वही 6 राज्य हैं जिनमें हम प्रक्रियाधीन ऋण दे रहे हैं?

सतनाम सिंह : ये आंकड़े सभी राज्यों के लिए हैं और उन 6 राज्यों का अलग–अलग ब्यौरा हमने तैयार नहीं किया है। सभी राज्यों का कुल मिलाकर कुल उधार – दीर्घावधिक ऋण लगभग 5800 करोड़ रुपए और अल्पावधिक ऋण लगभग 1890 करोड़ रुपए है। 6 राज्यों के लिए यह कम होगा।

संचालक : धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न इक्विरस सेक्शन के दिवांग मोदी की ओर से है। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

दिवांग मोदी : एसईबी को प्रक्रियाधीन ऋण प्रदान करने के लिए क्या कोई विशेष ब्याज दर है?

सतनाम सिंह : कोई विशेष दर नहीं, सामान्य दर।

दिवांग मोदी : सामान्य बाजार दर ही इस पर लागू होगी?

सतनाम सिंह : जी हां।

संचालक : यह अंतिम प्रश्न था। अब मैं सम्मेलन का मंच श्री कुणाल शाह को उनकी समापन टिप्पणियों के लिए देना चाहूंगा।

कुणाल शाह : महोदय, आपके समय और आपके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। महोदय, इस पुनर्गठन के 17,900 करोड़ रुपए के संबंध में एक बात यह है कि क्या यह पहली तिमाही में हुआ है या यह अगस्त में हुआ था।

सतनाम सिंह : पहली तिमाही में।

कुणाल शाह : इस पुनर्गठन से राशि के रूप में कितना लाभ हुआ। इस पुनर्गठन से कितने प्रतिशत बिन्दु और कितने आधारभूत बिन्दु की वृद्धि हुई?

सतनाम सिंह : लगभग 40 करोड़ रुपए।

कुणाल शाह : इस प्रकार मुश्किल से 20–25 बीपीएस की वृद्धि हुई है।

सतनाम सिंह : परन्तु पिछली तिमाही में 15,000 करोड़ रुपए का संवितरण जिसके लिए पहली तिमाही में पूरा राजस्व प्राप्त हुआ है और पुनर्गठन के लिए 17,900 करोड़ रुपए, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है।

कुणाल शाह : और आपने बताया कि अगली तीन तिमाहियों में रिप्राईसिंग के कारण परिसम्पत्तियों की ओर 17,000 करोड़ रुपए और देयताओं की ओर 24,000 करोड़ रुपए होंगे।

सतनाम सिंह : दूसरी तिमाही काफी सीमित है, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए लगभग 7000 और 9000 करोड़ रुपए।

कुणाल शाह : बिलकुल ठीक महोदय, इतना अधिक समय देने के लिए आपका धन्यवाद और कॉल में भाग लेने के लिए सभी भागीदारों का धन्यवाद। नमस्कार!

संचालक : धन्यवाद महोदय, ईडलवाइज सिक्योरिटीज लिमि. की ओर से मैं इस सम्मेलन का समापन करता हूं। भाग लेने के लिए धन्यवाद। अब आप अपनी लाइनों को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।

घोषणा

सामान्य घोषणा

यह दस्तावेज ईडलवाइज सिक्योरिटी लिमि. (ईडलवाइज) द्वारा तैयार किया गया है। ईडलवाइज इसकी धारक कंपनी और सहायक कंपनियां पूर्ण सेवा, समेकित निवेश बैंकिंग, पोर्टफोलियो प्रबंधन और ब्रोकरेज समूह हैं। हमारे अनुसंधान विश्लेषक और विक्रेता हमारी निवेश बैंकिंग गतिविधियों में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यह दस्तावेज इसी वित्तीय कागजात की खरीद या बिक्री या किसी सौदे की आधिकारिक पुष्टि के रूप में कोई प्रस्ताव या आग्रह नहीं है। इसमें दी गई सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों और अन्य स्रोतों, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है, से ली गई हैं परन्तु हम यह नहीं दर्शाते हैं कि यह सही और पूरी है और इस पर तद्नुसार भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ईडलवाइज या इसकी सहायक/समूह कंपनियों में से कोई भी इस रिपोर्ट में दी गई सूचना में किसी भूल से हुई त्रुटि से किसी व्यक्ति को होने वाले घाटे या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। यह दस्तावेज केवल सहायता के लिए दिया गया है और इसे किसी निवेश के लिए आधार के रूप में माना जाना उद्देशित नहीं है। प्रयोक्ता पर इस सूचना का कोई प्रयोग करने का पूरा जोखिम है। इस दस्तावेज का प्रत्येक प्राप्तकर्ता इस प्रकार की जांच करेगा, जिसे वह इस दस्तावेज में संदर्भित कंपनियों की प्रतिभूतियों में किसी निवेश के स्वतंत्र मूल्यांकन तक पहुंचने के लिए आवश्यक समझता हो (शामिल गुण–दोष और जोखिम सहित) और उसे ऐसे निवेश करने के गुण–दोष और जोखिम के निर्धारण के लिए अपने स्वयं के परामर्शदाताओं से परामर्श लेना चाहिए। चर्चा किया गया निवेश या व्यक्त किये गये विचार सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। हम और हमारे सहयोगी, समूह कंपनियां, अधिकारी, निदेशक और कर्मचारीः (क) समय–समय पर कंपनी में लंबी या छोटी स्थिति में और कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री कर सकते हैं या (ख) ऐसी प्रतिभूतियों में शामिल किसी अन्य सौदे में शामिल हो सकते हैं, दलाली या अन्य क्षतिपूर्ति अर्जित कर सकते हैं या ऐसी कम्पनी(यों) के लिए सलाहकार या ऋणदाता या कर्जदार के रूप में कार्य कर सकते हैं या किसी सिफारिश या संबंधित सूचना या राय के संबंध में अन्य संभावित हित विरोध को रख सकते हैं। यह सूचना अत्यंत गोपनीय है और केवल आपको आपकी सूचना के लिए दी जा रही है। इस सूचना को किसी अन्य व्यक्ति को पुनः प्रस्तुत या पुनः वितरित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से किसी भी रूप में नहीं दिया जाना चाहिए या किसी प्रयोजनार्थ पूर्ण या आंशिक रूप से प्रकाशित प्रतिलिप्यित नहीं किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को किसी ऐसे व्यक्ति या सत्ता द्वारा निर्देशित या वितरण अथवा प्रयोग के लिए आशयित नहीं किया गया है जो किसी ऐसे स्थान, राज्य, देश या अन्य अधिकार क्षेत्र का नागरिक या निवासी या उसमें रहता हो, जहां ऐसा वितरण प्रकाशन उपलब्धता या प्रयोग कानून, विनियम के विरुद्ध हो या जिसके कारण ईडलवाइज और संबद्ध/समूह कम्पनियां उस क्षेत्राधिकार के भीतर किसी पंजीकरण या लाइसेंसिंग अपेक्षाओं के अधीन होती हों। कपितय क्षेत्रों में इस दस्तावेज का वितरण कानून द्वारा प्रतिबंधित हो सकता है और वह व्यक्ति जिसके पास यह दस्तावेज हो, इनके बारे में सूचित करे और उन प्रतिबंधों का पालन करेगा। इस दस्तावेज में दी गई सूचना इस रिपोर्ट की तारीख के अनुसार है और इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि भावी परिणाम या घटनाएं इस सूचना से संगत होंगी। यह सूचना किसी पूर्व सूचना के बिना बदली जा सकती है। ईडलवाइज समय–समय पर जरूरत के अनुसार इस विवरण में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथापि ईडलवाइज पर इस सूचना को अद्यतन रखने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसके होते हुए भी ईडलवाइज अपने ग्राहकों को स्वतंत्र और पारदर्शी सिफारिशें प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राहकों के विशेष प्रश्नों के उत्तर में सूचना देकर उसे खुशी होगी। न तो ईडलवाइज और न ही उसकी सम्बद्ध कम्पनियां, ग्रुप कम्पनियां, निदेशक, कर्मचारी, एजेंट या प्रतिनिधि इस सूचना के प्रयोग से संबंधित या उससे होने वाले किसी घाटे या राजस्व में नुकसान सहित प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, विशेष या परिणामी किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। पिछला कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी कार्यनिष्पादन का मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। इस दस्तावेज के साथ संलग्न हितों के प्रकटन संबंधी विवरण केवल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराये गये हैं और इन्हें रिपोर्ट में व्यक्त विचारों का समर्थक नहीं माना जाना चाहिए। ईडलवाइज सिक्योरिटी लिमि. सामान्यतः अपने विश्लेषकों को जानकारी देने वाले व्यक्तियों और उनके आश्रितों को ऐसी प्रतिभूतियों या किसी कम्पनी के शेयरों जिसका उसके विश्लेषक अध्ययन करते हैं, में वित्तीय हित रखने से वर्जित करता है। इस दस्तावेज में प्रदत्त सूचना, जब तक अन्यथा बताई न जाये ईडलवाइज के प्रतिलिप्याधिकार में है, सभी रूपरेखा डिजाइन मूल कलाकृति संकल्पना और अन्य बौद्धिक संकल्पनाएं ईडलवाइज की सम्पत्ति और उसका प्रतिलिप्याधिकार हैं और इनका प्रयोग किसी पक्षकार द्वारा प्रतिलिप्याधिकार धारकों की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है।

विश्लेषकों का प्रमाणन :

इस रिपोर्ट के लिए विश्लेषक प्रमाणित करता है कि इस रिपोर्ट में व्यक्त सभी विचार संबद्ध कंपनी या कंपनियों और उसकी या उनकी प्रतिभूतियों के बारे में उसके व्यक्तिगत विचारों को प्रदर्शित करते हैं और उसकी क्षतिपूर्ति के किसी भी हिस्से को इस रिपोर्ट में विशिष्ट सिफारिशों या व्यक्त किये गये विचारों से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबंधित नहीं किया गया है या नहीं किया जायेगा।

स्टॉक में विश्लेषक की धारिता नहीं।

अमरीका के लोगों के लिए अतिरिक्त घोषणा

यह अनुसंधान रिपोर्ट ईडलवाइज सिक्योरिटी लिमि. का एक उत्पाद है जो अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने वाले अनुसंधान विश्लेषक(कों) का नियोजक है। अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने वाले अनुसंधान विश्लेषक(कों) अमरीका से बाहर के निवासी हैं और वे किसी विनियमित अमरीकी दलाल से संबद्ध नहीं है और इसलिए विश्लेषक(कों) अमरीकी ब्रोकर–डीलर के पर्यवेक्षण के अधीन नहीं है और उन्हें एफआईएनआरए की विनायमक लाइसेंसिंग अपेक्षाओं को पूरा करना अपेक्षित है या अन्य बातों के साथ किसी संबद्ध कम्पनी में संचार से संबंधित अमरीकी नियमों या विनियमों का अनुपालन करना होगा। सार्वजनिक उपस्थिति और व्यापार की गई प्रतिभूति किसी अनुसंधान विश्लेषक के खाते में रखी जायेगी।

यह रिपोर्ट ईडलवाइज सिक्योरिटी लिमि. द्वारा अमरीकी प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम 1934 (विनियम अधिनियम) के नियम 15 क–6(ख)(4) द्वारा यथापरिभाषित और नियम 15 क–6(ख)(4) के अनुपालन में अमरीकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा इसकी व्याख्या के अंतर्गत केवल "प्रमुख संस्थागत निवेशकों" को वितरित करने के लिए आशायित है। यदि इस रिपोर्ट का प्राप्तकर्ता ऊपर विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रमुख संस्थागत निवेशक नहीं होता है तो उसे इस रिपोर्ट के आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए और इसे भेजने वाले को लौटा देना चाहिए और इसके अलावा इस रिपोर्ट की किसी ऐसे अमरीकी व्यक्ति जो प्रमुख संस्थागत निवेशक नहीं है, द्वारा प्रतिलिपि, नकल और/या आगे संचार नहीं किया जा सकता है।

प्रमुख संस्थागत निवेशकों के साथ कतिपय व्यापार करने की दृष्टि से विनियम अधिनियम के नियम 15 क–6 द्वारा प्रदत्त पंजीकरण और उसकी व्याख्या से छूट पर भरोसा करते हुए ईडलवाइज सिक्योरिटी लिमि. अमरीकी

पंजीकृत ब्रोकर – डीलर मार्को पोलो सिक्योरिटीज आईएनसी ("मार्को पोलो") के साथ इस करार में शामिल हुए हैं।

इस अनुसंधान रिपोर्ट में चर्चा किये गये प्रतिभूतियों के सौदे मार्को पोलों या किसी अन्य अमरीकी पंजीकृत ब्रोकर डीलर के माध्यम से दिये जाने चाहिए।

प्रतिलिप्याधिकार 2009 ईडलवाइज रिसर्च (ईडलवाइज सिक्योरिटी लिमि.) सर्वाधिकार सुरक्षित।